Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 11-2019] CHANDIGARH, TUESDAY, MARCH 12, 2019 (PHALGUNA 21, 1940 SAKA)

PART-I A

Notifications by Local Government Department

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 28 फरवरी, 2019

संख्या 14/5/2017-3C-II.— हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम 24) की धारा 84 की उप धारा (1) के साथ पटित धारा 69 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियों), अधिसूचना संख्या का० आ० 86/ह० अ० 24/1973/धा० 69/2013, दिनांक 11 अक्तूबर, 2013 में निम्नलिखित संशोधन तुरंत प्रभाव से करते हैं, अर्थात्–

संशोधन

हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियों), अधिसूचना संख्या का०आ० 86/ह० अ० 24/1973/धा० 69/2013, में–

1. पैरा 5 में, उप पैरा (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

(ख) देरी से अदायगी की दशा में, प्रतिमाह 1.5 प्रतिशत की दर से ब्याज या उसका भाग प्रभारित किया जाएगा– परन्तु वर्ष 2010–11 से 2017–18 तक के लिए सम्पति कर के बकाया पर सम्पूर्ण ब्याज की एक मुश्त छूट सभी कर दाताओं को अनुमत होगी, यदि 31.03.2019 तक उनके बकाया भुगतान कर दिए जाते हैं।

2. जो सम्पति मालिक सम्पति कर का भुगतान कैशलैस तरीके से करवायेगा, उसे 1 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट प्रदान की जायेगी।

आनन्द एम० शरण,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 28th February, 2019

No. 14/5/2017-3C-II.— In exercise of the powers conferred by clause (1) of the Section-69 read with Sub – section (1) of the Section 84 of the Haryana Municipal Act,1973 (24 of Act 1973), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government. Urban Local Bodies Department (Committees). Notification No. S.O. 86/H.A.24/1973/S.69/2013, dated the 11th October, 2013, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees) Notification No. S.O.86/ H.A. 24/1973/S.69/2013, dated the 11th October, 2013.

1. In Para 5, for sub-Para (b),the following sub-Para shall be substituted, namely:-

(b) in case of late payment, interest at the rate of 1.5% per month or part thereof shall be charged: Provided that one time complete waiver of interest on dues and arrears of property tax pending since year 2010-11 to 2017-18 shall be allowed to all tax payers, if their arrears are paid upto 31.03.2019.

2. 1% rebate shall be given to property owner who will pay the property tax by cashless system.

ANAND M. SHARAN,
Principal Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.

56916—C.S.—H.G.P., Chd.